समक्ष जे.वी गुप्ता, जे.

धनी राम- याचिकाकर्ता

बनाम

अध्यक्ष, हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड- उत्तरदाता

नियमित द्वितीय अपील संख्या 1144/1976

2 अगस्त 1984

हरियाणा सरकार विद्युत उपक्रम (बकाया वसूली) अधिनियम (1970 का XXIX) - धारा 4 और 5 - विद्युत उपक्रम द्वारा कथित रूप से मांगी गई अतिरिक्त राशि - विरोध के तहत जमा की गई ऐसी राशि - जमा की तारीख से छह महीने से अधिक की राशि की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया गया -इस बात का कोई सबूत नहीं है कि धारा 4 के तहत मांग का कोई नोटिस दिया गया था-मुकदमा-क्या समय से बाधित माना जा सकता है।

माना गया कि, हरियाणा सरकार विद्युत उपक्रम (बकाया वसूली) अधिनियम, 1970 की धारा 5 की उपधारा (1) की भाषा से, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि जब अधिनियम की धारा 4 के तहत मांग का नोटिस दिया गया है, तभी जमा की तारीख से छह महीने के भीतर सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर किया जा सकता है। जहां यह साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं है कि ऐसा कोई मांग नोटिस जारी किया गया था, यह नहीं माना जा सकता है कि जमा की तारीख से छह महीने से अधिक समय तक दायर किया गया मुकदमा अधिनियम की धारा 5 के तहत वर्जित था। (पैरा 5)

श्री हरि राम, वरिष्ठ उप-न्यायाधीश (बढ़ी हुई अपीलीय शक्तियों के साथ), करनाल के न्यायालय के आदेश से नियमित दूसरी अपील, दिनांक 20 अगस्त, 1975, श्री एसडी अरोड़ा, उप-न्यायाधीश, द्वितीय श्रेणी, कैथल के आदेश की पुष्टि करते हुए, दिनांक 1 अगस्त, 1973 को वादी के मुकदमे को लागत सहित खारिज कर दिया गया।

अपीलकर्ता की ओर से वी.के. जैन, अधिवक्ता।

हनवंत सिंह हुडा, अधिवक्ता, प्रतिवादी।

निर्णय

जे.वी गुप्ता, जे.

1. यह वादी की दूसरी अपील है जिसका 841 रुपये की वसूली का मुकदमा नीचे की दोनों अदालतों द्वारा समय से बाधित होने के कारण खारिज कर दिया गया है।
2. वादी ने प्रतिवादी द्वारा गलत तरीके से वसूले गए 841 रुपये की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया। वादपत्र के पैराग्राफ 4 में यह निवेदन किया गया कि वादी को मीटर में खराबी के कारण अधिक चलने के लिए 28 दिसंबर 1970 को 841 रुपये की राशि जमा करनी पड़ी और उक्त राशि मजबूरी में जमा की गई थी। वादपत्र के अनुसार, वादी को 28 दिसंबर 1970 को उपमंडल अधिकारी, हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड, पेहोवा के कार्यालय में 841 रुपये की राशि जमा करने की तिथि पर मामला उत्पन्न हुआ था। प्रतिवादी बोर्ड की ओर से दायर लिखित बयान में एक प्रारंभिक आपत्ति ली गई थी और यह दलील दी गई थी कि मुकदमा समय से बाधित है। गुण-दोष के आधार पर भी, वादी में लगाए गए आरोपों का खंडन किया गया। पक्षों की दलीलों पर टायर ट्रायल कोर्ट ने आवश्यक मुद्दे तय किए। मुद्दा क्रमांक 1 इस आशय का था कि क्या मुकदमा कालबाधित है? इस मुद्दे को प्रारंभिक मुद्दे के रूप में माना गया और पार्टियों ने इस मुद्दे पर कोई सबूत नहीं दिया। विद्वान ट्रायल कोर्ट के अनुसार, इस तरह का मुकदमा दायर करने की सीमा हरियाणा सरकार विद्युत उपक्रम (बकाया वसूली) अधिनियम 1970 की धारा 5 के तहत जमा की तारीख से छह महीने थी, जबकि माना जाता है कि मुकदमा 11 अक्टूबर 1972 को दायर किया गया था जो जमा करने की तिथि से छह माह से अधिक का था। परिणामस्वरूप, उनकी रिट को समय-बाधित मानकर खारिज कर दिया गया। अपील में, विद्वान वरिष्ठ अधीनस्थ न्यायाधीश ने बढ़ी हुई अपीलीय शक्तियों के साथ प्रारंभिक मुद्दे पर ट्रायल कोर्ट के उक्त निष्कर्ष की पुष्टि की और, इस प्रकार, वादी के मुकदमे को खारिज करने वाले डिक्री को कायम रखा। इससे असंतुष्ट होकर उन्होंने इस न्यायालय में यह दूसरी अपील दायर की है।
3. अपीलकर्ता के वकील ने कहा कि अधिनियम की धारा 5, इस मामले पर लागू नहीं था क्योंकि इसके तहत विचार किया गया मुकदमा एक था जहां देनदार पर धारा 4

के तहत बकाया के लिए मांग का नोटिस दिया गया था और विरोध के तहत राशि जमा की गई थी, लेखन में, और कर्जदार ने उक्त बकाये का भुगतान करने के लिए अपनी देनदारी का मुकाबला किया। विद्वान वकील के अनुसार, यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं था कि अधिनियम की धारा 4 के तहत निर्धारित प्रारूप में कोई भी मांग नोटिस, वादी को कभी जारी किया गया था। वादी के अनुसार उसे केवल वह बिल जारी किया गया जिस पर विरोध स्वरूप धनराशि जमा की गई थी। इस प्रकार, विद्वान वकील ने तर्क दिया, अधिनियम की धारा 5 इस मामले के तथ्यों पर बिल्कुल भी लागू नहीं थी और वर्तमान मामले में, सीमा अधिनियम के तहत मुकदमा दायर करने की सीमा जमा की तारीख से तीन साल थी।

4. पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, मुझे अपीलकर्ता की ओर से उठाए गए तर्क में दम नजर आया।

5. अधिनियम की धारा 5 में लिखा है,-

"5. भुगतान के दायित्व को चुनौती देने के लिए मुकदमा - (1) जहां धारा 4 के तहत देनदार या उसके अधिकृत एजेंट को मांग का नोटिस दिया गया है, यदि वह बकाया राशि, जुर्माना या लागत या इनमें से किसी भी हिस्से का भुगतान करने के अपने दायित्व से इनकार करता है तो वह ऐसा कर सकता है। उन्हें निर्धारित प्राधिकारी के पास मांग की सूचना में निर्दिष्ट कुल राशि को लिखित रूप में विरोध के तहत जमा करने के बाद कि वह इसका भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, इस प्रकार जमा की गई बकाया राशि या उसके हिस्से की वापसी के लिए मुकदमा दायर करें।
(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट एक मुकदमा निर्धारित प्राधिकारी के पास जमा करने की तारीख से छह महीने के भीतर किसी भी समय सक्षम क्षेत्राधिकार वाले सिविल न्यायालय में स्थापित किया जा सकता है और ऐसे मुकदमे के परिणाम के अधीन, नोटिस मांग का विवरण उसमें उल्लिखित विभिन्न बकाया, जुर्माना और लागत का निर्णायक प्रमाण होगा"

धारा 5 की उपधारा (1) की भाषा से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि जब अधिनियम की धारा 4 के तहत मांग की सूचना दी गई हो, तभी छह महीने के भीतर सिविल न्यायालय में मुकदमा दायर किया जा सकता है। जमा की तारीख. बेशक, वर्तमान मामले में, यह साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं है कि अपीलकर्ता को ऐसा कोई मांग नोटिस जारी किया गया था। ऐसे किसी सबूत के अभाव में, यह नहीं माना जा सकता कि वादी का मुकदमा अधिनियम की धारा 5 के तहत वर्जित था। इस संबंध में निचली अदालतों का दृष्टिकोण गलत और अवैध है।

6. मामले के इस दृष्टिकोण से, यह अपील सफल होती है और लागत के साथ स्वीकार की जाती है। पक्षों को सबूत पेश करने की अनुमति देने के बाद परिसीमा के मुद्दे सहित सभी मुद्दों पर नए फैसले के लिए मामले को ट्रायल कोर्ट में भेज दिया गया है। पक्षों को 5 सितंबर 1984 को ट्रायल कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। मामले के रिकॉर्ड तुरंत वापस भेजे जाएं। चूंकि वर्तमान मुकदमा वर्ष 1972 में दायर किया गया था, इसलिए यह निर्देशित किया जाता है कि इसका निपटान शीघ्र किया जाए; अधिमानतः छह महीने के भीतर ।

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

आशीष कुमार मंडल
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
फिरोज़पुर झिरका, नूंह